Besides three tankers, six trucks and one tempo involved in above said cases were also seized.

(d) Cases against the offenders have been registered under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955 and the orders issued thereunder and prosecutions have been launched against them. In all 164 persons have been arrested so far.

(e) Government is at present considering no change in legal procedure. However, all State Governments have been advised to set up new courts or earmark the existing ones to expedite the disposal of cases under the Essential Commodities Act, 1955.

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर

485. **श्री रामलाल राही** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश के विभिन्न भागों में प्रतिदिन काम में लाई जाने वाली कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी अन्तर है और अनुचित लाभ कमाने वाले व्यक्ति उनके मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि करके लोगों का शोषण कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ही प्रकार की वस्तुओं को समान निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए निर्णय करने के प्रश्न पर विचार करने का है जिससे शोषण और अनुचित लाभ को रोका जा सके ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख)। देश के विभिन्न भागों में रोजमर्रा के उपयोग की विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर है, जिसका मुख्य कारण उत्पादों की किस्मों में भिन्नता होना, स्थानीय करों, ढुलाई लागत तथा मांग व आपूर्ति की स्थितियों में अन्तर होना है ।

चीनी के मामले में दोहरी मूल्य प्रणाली फिर से लागू करने से यह देश भर में उचित दर की दुकानों के माध्यम से एक समान मूल्य पर बेची जा रही है । उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों के मामले में भी केन्द्रीय निर्गम मूल्य एक समान हैं, हालांकि वे उपभोक्ताओं को उन मूल्यों पर बेचे जाते हैं जो अलग-अलग राज्यों में मामूली तौर पर अलग-अलग हो सकते हैं । औषधियों के मूल्य भी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और स्थानीय करों को छोड़ कर देशभर में उनके मूल्य एक समान हैं। यही सिद्धान्त कमोडेस बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम, 1977 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर भी लागू होता है । इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने तथा उनके संचालन में सुधार करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ; ताकि देश भर में वे उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र, जनसंख्या व वस्तुओं को लाकर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है । इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके अनुसार देश भर में उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुयें एक समान मूल्यों पर उपलब्ध की जायें ।

Revision of Import Policy

486. SHRI JAI NARAIN: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that new Government at the Centre propose to revise the existing import policy of the country; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b). The import policy is announced for each financial year April to March. The import policy for the next year i.e. April 1980—March 1981 is under formulation. It is not possible to give details of the new import policy at this stage.

Indo-U.S. Joint Business Council

487. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the positive outcome of the meeting of Indo-U.S. Joint Business Council held recently in New Delhi;

(b) whether it is a fact that the Leader of the U.S. Delegation to the Indo-U.S. Joint Business Council, Mr. Orville L. Freeman, had expressed in the said meeting, the hope that